जाए । ऐसा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा मकसद था वह इससे सर्व नहीं होगा। फिर रात को एक्सचेंज ब्लाक हुआ करेंगे ।

श्री प्रमोद महाजन : फिर आप एस० टी० डी० में क्यों करते हैं ? दिनभर एक ही रेट लगा दीजिए । कनैक्शन कम करना है तो जैसे एस०टी०डी० में है वैसे लोकल कॉल्स में कर दीजिए ।

श्री राजेश पायलट : आपके विचार मैंने ध्यानपूर्वक सुने । मैं इस बारे में सोचूंगा और इसमें क्या कुछ हो सकता है, वह मैं आपको इत्तला करूंगा ।

उपसभापति : सैयद सिब्ते रजी । आई थिंक अब इसमें कुछ नहीं है ।

श्री सैयद सिब्ते रजी : एक बात मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि वह कौन-कौन से नगर हैं जहां आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है और नंबर दो जैसा महाजन जी ने कहा कि डिस्करेज करना चाहिए कि लंबी बात ज्यादा देर तक नहीं चलनी चाहिए । तो क्या इस बात पर भी विचार हो रहा है कि अगर 5 मिनट के बाद बात होगी तो रेट्स उससे कुछ बढ़ जाएंगे ?

श्री राजेश पायलट : हमने हिदायत मंदी थी कि 16 जून से यह स्कीम लागू होनी चाहिए लागू 31 जुलाई तक सारे देश में लागू हो जानी चाहिए जहां पर यह स्कीम लागू की गई है वे शहर हैं—दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलौर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, गाजियाबाद, लुधियाना, कानपुर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, त्रिवेन्द्रम, नागपुर, अमृतसर, पटना, 22 ऐसी जगह हैं जहां लागू हो गई है और बाकी जगह 31 जुलाई तक लागू होने के आदेश हैं ।

दूसरा सवाल माननीय सदस्य का था कि 5 मिनट के बाद क्या रेट बढ़ जाएगा ? ऐसा कुछ नहीं है पांच मिनट की एक यूनिट हो जाएगी लेकिन रेट वही रहेगा । अगर आप 20 मिनट बात करेंगे तो चार यूनिट चार्ज की जाएंगी, रेट उसी हिसाब से है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश में मुख्य डाकघरों के भवनों का निर्माण

*84. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के किन-किन शहरों में मुख्य डाकघरों के भवनों के निर्माण के लिए पोस्टमास्टर जनरल (महा डाकपाल) हिमाचल परिमंडल धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया था ;

(ख) किन-किन मुख्य डाकघरों के मामले में भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्रत्येक मामले में स्वीकृति किस-किस तारीख को दी गई ; और

(ग) किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है और किन-किन स्थानों पर वर्ष 1992-93 में निर्माण कार्य शुरू किए जाने की योजना है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The names of the cities of Himachal Pradesh in respect of which the Postmaster General Himachal Pradesh Circle had urged for provision of funds for the construction of Head Post Office buliding during 1991-92 and 1992-93 are:

(1) Nahan

(2) Rekong Peo

(3) Kullu.

(b) Stations for building construction

have been issued in the following cases:

Name of Head Post Office	Date of issue of sanction
Nahan	3-3-1989
Rekong Peo	14-5-1992

(c) The construction work of Nahan Head Office building is in progress. The construction of Rekong Peo building is likely to start durig 1992-93.

In addition, the following projects are in progress:—

1. Circle Office-cum-Dy. Director of Accounts Postal's Office, Shimla.
2. Divisional Office, Solan.
3. Dalhosie P.O., Holiday Home & 2 Nos. Type II Qrs.
4. Pragpur P.O. (Kangra)
5. Bihjari P.O. (Hamirpur)
6. Chaundra P.O. (Mandi)
7. Garrage at Cart Round Shimla.

Staff Quarters :

1. Nahan 4 type-I
2. Una 3 type-II and 3 type-III
3. Shimla type-I, 16, II, 14, III, 15, IV, 6, V 2.
4. Shimla type-II 16, III 8
5. Downdale, Shimla (Joint Project) postal Share type—18.

श्री महेश्वर सिंह : महोदया, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उसके अनुसार पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश ने तीन स्थानों के लिए धन की व्यवस्था का आग्रह किया था। उसमें से जहां तक नाहन का संबंध है, निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जहां तक रिकोंग पीओ का संबंध है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह निर्माण कब शुरू होगा और जहां तक कुल्लू का संबंध है आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि 19 दिसंबर, 1990 को तत्कालीन संचार मंत्री महोदय से मैंने पत्र द्वारा आग्रह किया था कि कुल्लू में भी समस्या है और वहां पर भवन का निर्माण होना चाहिए और उन्होंने मेरे पत्र के उत्तर में यह लिखा था कि निर्माण कार्य के लिए 35 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वहां पर निर्माण कार्य आरंभ करने की स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं और कब यह स्वीकृति दी जाएगी ताकि वहां निर्माण कार्य हो सके ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैडम, माननीय सदस्य ने रिकोंग पीओ की बात कही है। यहां का काम इसी साल में हमने रखा है और 1992-93 में यह काम फाइनेंसियल बजट में रखकर इसे पूरा करवाने के आदेश हमने दिए हैं। जहां तक कुल्लू की बात है, वहां एक समस्या थी कि पुरानी बिल्डिंग में जहां काम हो रहा है, उसमें कुछ मोडिफिकेशन होना था और कुछ तोड़कर नयी इमारत बनाने का प्रस्ताव था। उसकी ड्राइंग तैयार हो गई है। मुझे माननीय सदस्य का जो पत्र मिला था, उसके बाद मैंने आदेश दिए हैं

ड्राइंग्ज पास हो गई है, बजट पास हो गया है और हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी साल में इन्क्लूड कराकर काम चालू करवायें ।

मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट के बढ़ने से हमें कम्युनिकेशन में प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसीलिए जब मुझे पता चला कि मनाली में एस. टी. डी. नहीं है तो हमने विशेष कदम उठाए और यह देखा कि जहां जरूरत है वहां पर आदेशों का इंतजार न किया जाए, अपने आप इनिशिएटिव लेकर अधिकारी ऐसे कदम उठाएं जो विभाग के और जनता के हित में है । तो इन तीनों चीजों को दिखवाकर मैं कोशिश करूंगा कि इसी 1992-93 में कंपलीट कराया जाए ।

श्री महेश्वर सिंह : मैं आप से जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में और कौन-कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर हैड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है और मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जहां तक हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों का संबंध है विशेष कर लाहौलस्फीति के मुख्यालय केलंग का संबंध है वहां पर न तो सरकारी भवन पोस्ट ऑफिस के लिए है न कोई आवास की सुविधा उपलब्ध है । वे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि वर्ष में कम से कम 6 महीने तक बर्फ से लगभग ढ़के रहते हैं । तो क्या मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी विभाग को ऐसे आदेश प्रदान करेंगे कि धन का प्रावधान ऐसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी किया जाए ताकि वहां पर भवन निर्माण का कार्य किया जा सके ?

श्री राजेश पायलट : मैडम जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है 17 हैड पोस्ट आफिसेज में से तकरीबन 15 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में है । दो जगह ऐसी हैं जहां यह काम चल रहा है—नाहन और रिकोंग पीयो । इन पर सेक्शन हो गया है । हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर हमारे हैड पोस्ट ऑफिसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है । छोटे सब पोस्ट आफिसेज एक्सट्रा डिपार्टमेंटल आफिसेज ज्यादातर प्राइवेट हायर एकोमोडेशन में है । एक समस्या जो विभाग के सामने है वह यह है कि हमारा टोटल एलोकेशन 121 करोड़ का सारे देश के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में है । हर जगह से इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं । क्योंकि अब रेट्स बढ़ गए हैं हमने जो डाकखाने के लिए जगह प्राइवेट हायर कर रखी है उनके मालिक पुराने रेट पर देने को तयार नहीं हैं । कहते हैं कि खाली करो । हमारे लिए उससे समस्या बनी हुई है । लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे विभाग के आफिसेज खासकर हैड आफिसेज सरकारी बिल्डिंगों में जाएं जिससे रोज-रोज लोगों की ये शिकायतें सामने न आयें ।

श्री महेश्वर सिंह : मैंने जनजाति क्षेत्र के बारे में पूछा था ।

श्री राजेश पायलट : खास जगह के लिए मैं माननीय सदस्य को अलग से इत्तला दे दूंगा ।

Government control over functioning of Foreign Banks in India

*85. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government exercises any control over functioning of foreign banks in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.